



गांव

हमारा



चौपाल से
भीपाल तक

भीपाल, सोमवार 27-03 जुलाई 2022, वर्ष-8, अंक-12

भीपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुँरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्य:- 2 रुपए

तैदूपता बेंचने और तोड़ने का अधिकार भी जनजतीय वर्ग को मिलेगा

एक लाख आदिवासी युवाओं को नौकरी देगी शिवराज सरकार

भीपाल।

शिवराज सरकार एक लाख आदिवासी युवाओं को नौकरी देगी। साथ ही मध्यप्रदेश में पायलट बेस पर तैदूपता बेंचने और तोड़ने का अधिकार भी जनजतीय वर्ग को मिलेगा। ये ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने पर पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताने के लिए हुए कार्यक्रम में किया। कार्यक्रम

में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, संपतिया उड्के, वन मंत्री विजय शाह, मंत्री फगन सिंह कुलसते मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि आदिवासी समाज से एक लाख युवाओं को रोजगार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही पायलट बेस पर तैदूपता बेंचने और तोड़ने का अधिकार भी जनजतीय वर्ग को मिलेगा। हमने तय किया है।



आज से एक नई क्रांति शुरू हो रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी चुन-चुन के जनजाति नायक को पत्र श्री देने का काम किया है। आज मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूँ। एक नयी क्रांति हो रही है। जो समाज रह गए थे उन्हें देश का भविष्य बनाया जा रहा है। ये मध्यप्रदेश के दो करोड़ आदिवासी जनजाति भाई बहनों का सम्मान है। कांग्रेस हमने आदिवासी को सम्मान दिया है। पैसे ऐक्ट अब धीरे धीरे लागू हो रहा है। हमने तय किया पायलट बेस पर तैदूपता बेंचेंगे और खरीदेंगे।

मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिए मांगी अनुमति

सीएम ने मांगी चार लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति

भीपाल।

गर्मी के मौसम में किसानों के द्वारा लगाई गई मूंग की कटाई होने के बावजूद भी अभी तक इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है। जिसके चलते किसानों को मूंग का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। 21 जून को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से कृषि भवन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर मध्यप्रदेश में उपाजन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल को अवगत कराया कि प्रदेश में फसल विविधीकरण में दलहन फसलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस वर्ष प्रौद्योगिकी मूंग का उत्पादन 16 लाख मीट्रिक



टन होने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अधिक उत्पादन के कारण प्रौद्योगिकी मूंग का प्रचलित बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला गया है। केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल से अनुरोध किया कि उत्पादन में वृद्धि और किसानों के हित देखते हुए विपणन वर्ष 2022-23 में प्राइस स्टेबिलिटी फण्ड से मूंग के कुल उत्पादन 16 लाख मीट्रिक टन की 25 प्रतिशत मात्रा 4 लाख मीट्रिक टन के उपाजन की अनुमति प्रदान की जाए।

वया है मामला

सरकार द्वारा पूर्व में घोषित मूंग एवं उड़द के समर्थन मूल्य पर ही गर्मी (जायद) सीजन की मूंग एवं उड़द की खरीदी की जानी है, जो मूंग के लिए 7,275 रुपये प्रति क्विंटल तथा उड़द के लिए 6,300 रुपये प्रति क्विंटल है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष 2020-21 में राज्य के किसानों से मूंग एवं उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर की थी। जिसमें प्रदेश में पिछले वर्ष 4 लाख 39 हजार 563 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी 301 केन्द्रों से की गई थी। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के लक्ष्य से तीन गुना अधिक खरीदी की थी, जिसमें कुल 1 लाख 85 हजार किसानों से मूंग की खरीदी की गई थी।

राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन में बोले केन्द्रीय राज्य मंत्री

बाजरा भारत का सुपर फूड: प्रहलाद सिंह पटेल

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में 'भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड' विषय पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन उद्योग निकाय एसोसिएम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया। इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया। सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर

17.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था और बाजरा (मोती बाजरा) का उत्पादन भी इसी अवधि में बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है।



राष्ट्रीय सम्मेलन में बाजरा के फायदों के बारे में बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि बाजरा देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक रहा है। यह छोटे बीजों से उगाई जाने वाली फसल है जिसे शुष्क क्षेत्रों में या यहां तक कि कम उर्वरता वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है। यही कारण है कि इसे भारत के सुपरफूड के रूप में जाना जाता है।

फर्टिलाइजर व कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने पिर दिया जोर, केन्द्रीय कृषि मंत्री ने 11वें एग्रीकेमिकल्स कान्क्लेव को संबोधित किया

कीटनाशकों पर कम होगी जीएसटी, कृषि मंत्री ने दिया आश्वासन

नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खेती में फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। श्री तोमर ने यह बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्को) द्वारा आयोजित 11वें एग्रीकेमिकल्स कान्क्लेव को सोलन (हिमाचल प्रदेश) से वर्चुअल संबोधित करते हुए कही। तोमर ने कहा कि उद्यानिकी को भी और बढ़ाना चाहिए ताकि हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बन सकें। खाद्यान की दृष्टि से हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए हमें कृषि की दृष्टि से विकसित अन्य देशों की ओर भी देखना होगा।



कीटनाशकों पर जीएसटी होगी कम

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि-रसायन उद्योग को आश्वासन दिया कि वह वित्त मंत्री के साथ कीटनाशकों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की उद्योग की मांग को उठाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में होगी। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने फसल

विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि किसानों को अधिक बागवानी और महंगी फसलें उगानी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हुए यह कहा कि एग्रीकेमिकल्स पर 18 प्रतिशत का जीएसटी अत्यधिक अनुचित है क्योंकि वे न केवल फसल स्वास्थ्य के लिए बीमा के रूप में कार्य करते हैं बल्कि किसानों की गुणवत्ता, उपज और आय में भी वृद्धि करते हैं।

कृषि रसायन पर जोर

पूर्व कृषि आयुक्त डॉ. चारुदत्त रिगंबर माई ने कहा कि एग्रीकेमिकल्स उद्योग हमारे किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है और फसल के नुकसान को कम करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ उच्च उपज का आश्वासन देता है। जलवायु परिवर्तन और कीटों और बीमारियों के उभरते खतरों को देखते हुए, नए और नवीन रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के लिए नियामक प्रणाली को बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

सफल मत्स्य पालन के लिये उचित प्रबंधन

डॉ. माधुरी शर्मा, सह प्राध्यापक
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं पशुपालन
विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर, म.प्र.

जबलपुर, विश्व एवं देश पर निरन्तर बढ़ रहे जनसंख्या दबाव से निपटने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना तो आवश्यक है ही, परन्तु इसके साथ-साथ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही कुपोषण एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इन समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ी जायें और दूसरा तरीका है कि इन मछलियों का पालन करके अधिक-से अधिक उत्पादन किया जाए।

देश में निहित जल संसाधन, मत्स्य जैविकों की विविधता की पर्याप्तता होने के उपरान्त भी औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2100 किग्रा प्रतिवर्ष है जबकि वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर उत्पादन को प्रति इकाई 6-8 गुना बढ़ाया जा सकता है। कम उत्पादकता का मुख्य कारण मत्स्य पालकों का वैज्ञानिक विधियों से परिचित न होना है। गतिविधियों जैसे सही समय पर नर्सरी तालाब की तैयारी, कीटों का उन्मूलन, बीज संचयन, परिपूरक आहार का सही मात्रा में प्रयोग करे तो निश्चित ही मत्स्य उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।

मत्स्य पालन के लिये पूर्व तैयारी- तालाब के लिये उपयुक्त स्थान का चयनकर मृदा का विश्लेषण कराते हैं। जिससे मिट्टी के प्रकारों का उसके अवयवों (क्ले, सिल्ट एवं सेन्ड) का सही प्रतिशत पता करते हैं जिससे सही स्थान पर तालाब बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त जल एवं मिट्टी की अम्लीयता एवं क्षारीयता का पता लगाते हैं। पी.एच. मान का सीधा प्रभाव तालाब की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। मछली पालन के लिये कम अम्लीय जल से कम क्षारीय जल उपयोगी होता है। जल की अम्लीयता को चुने के प्रयोग द्वारा तथा कम क्षारीयता को जिप्सम के प्रयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

मत्स्य बीज (मेजर कार्प)- मछलियाँ प्राकृतिक रूप से बढ़ते हुये जल में प्रजनन करती हैं, उत्पादित बीज एकत्र करते हैं, परन्तु तालाब में संचय पूर्व प्रजाति की एकरूपता को सुनिश्चित करना चाहिए।



सारिणी-1
जलीय खरपतवार एवं नियंत्रण के लिये उपयोगी रसायन

जलीय खरपतवार	जल में उपस्थिति रसायन
1. पिस्टिया	सतह पर तेरने वाले खरपतवार
2. जलकुम्भी	सतह पर तेरने वाले खरपतवार
3. साल्वीनिया	सतह पर तेरने वाले खरपतवार
4. हाईड्रिला	जलमगनीय खरपतवार
5. निम्फिया	जलमगनीय खरपतवार
6. नीलम्बो	जलमगनीय खरपतवार
7. आइसोमिया	छिदले जल में पाये जाने वाले खरपतवार

निषेचन के पश्चात् हैचरियों में लगभग तीन दिनों में स्थान बनकर तैयार हो जाते हैं, इन जिरों को प्राकृतिक भोजन से परिपूरक नर्सरी तालाब में संचय कर देते हैं। इस दौरान प्लवकों का पयाज्ज स्तर निरन्तर बनाये रखने के लिये जैविक एवं रसायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। लगभग एक महीने में एक बार जाल चलाकर मत्स्य स्वास्थ एवं वृद्धि दर की जाँच करते रहना चाहिए।

प्रबंधन- जलीय खरपतवारों का, अर्वाञ्छनीय मछलियों का, जलीय कीटों का नियंत्रण करते हैं। खरपतवार में हाईड्रिला, नीलम्बो वेलिसरिया, पोटेमोजिटोन, जलकुम्भी, आइकारनिया प्रमुख हैं, इन्हें मानव श्रम लगाकर जड़ से उखाड़कर सुखाकर जला देना चाहिए। यदि तालाब बड़ा है तथा इनकी

सारिणी-2

उर्वरक	मात्रा	समय
1. गाय का गोबर	1000-1500 किग्रा. प्रति हेक्टेयर	मसिक
2. यूरिया	20-30 किग्रा. प्रति हेक्टेयर	मसिक
3. सिंगिल सुपर फॉस्फेट	20-30 किग्रा. प्रति हेक्टेयर	वार्षिक
4. अमोनियम सल्फेट	300-400 किग्रा. प्रति हेक्टेयर	मसिक

मात्रा बहुत अधिक है तब मानव श्रम द्वारा इन जलीय खरपतवारों का

उन्मूलन सम्भव नहीं हो पाता है तब हम विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके इनका नियंत्रण करते हैं जो सारिणी में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त जलमगनीय वनस्पतियों का नियंत्रण जैविक विधि, ग्रास कार्प द्वारा किया जा सकता है। जो इन वनस्पतियों को खाती हैं। इसी प्रकार टिलापिया मछली भी जलीय वनस्पति (खरपतवार) का भक्षण करती है।

मत्स्य बीज का संग्रहण- संग्रहण के पूर्व जल के विषेलेपन की जाँच तथा प्लवक स्तर की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये कुछ फिंगरलिंस को 48 घण्टों के लिये तालाब में हापा लगा कर छोड़ दिया जाता है। अगर इस विधि में

फिंगरलिंस सकुपल रहते हैं तो तालाब के जल को मछलियों के लिये उपयुक्त मानना चाहिये। इस अवस्था में प्लवक ही मछली का मुख्य भोजन होता है अतः जल में प्लवकों की मात्रा कम से कम 2 सेमी. प्रति 50 मिली. होनी चाहिए।

संग्रहण सघनता- च्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिये मछलियों के संचय के समय उनका आकार एवं संख्या दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 8-30 मिमी. की फ्राई को 10,000-15,000 प्रति हेक्टेयर की दर से तथा 50-150 मिमी. की फिंगरलिंस को 5000-6000 प्रति हेक्टेयर की दर से संग्रहण करना उपयुक्त रहता है। फिंगरलिंस के संग्रहण के लिये प्रातःकाल का समय उपयुक्त रहता है। तालाब में फिंगरलिंस छोड़ने से पूर्व फिंगरलिंस के पात्र या थैली को तालाब के जल में कुछ समय तक डुबाकर रखना चाहिये जिससे दोनों का तापमान एक जैसा हो जाए। कुछ समय के उपरान्त धीरे-धीरे फिंगरलिंस को तालाब में छोड़

देना चाहिये।

संग्रहण के पश्चात् प्रबंधन -तालाब में प्राकृतिक जैविक आहार बराबर उपलब्ध रहे इसके लिये नियमित उर्वरीकरण करते रहना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग निम्न प्रकार से करना चाहिए-

सामान्यतया मछली पालने के एक वर्ष बाद निकासी की जाती है। जिसके लिये या तो खींचने वाले जाल का प्रयोग किया जाता है या फिर तालाब के जल को निकालकर निकासी की जाती है। यदि तालाब का नियमित समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित किया गया हो तो 10,000-15,000 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मत्स्य पालन को वैज्ञानिक तकनीक एवं व्यवस्थित रूप से करने पर मत्स्य उत्पादन बढ़ा कर हम भोजन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तथा अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी सलाह

टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.एस. किरार, वैज्ञानिक, डॉ. आई.डी. सिंह, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ. एस.के. जाटव द्वारा किसानों को खरीफ फसलों की विपुल उत्पादन हेतु समसामयिकी सलाह दी गयी। जिले में खरीफ मौसम में मुख्यतः उड़द, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, ज्वार की खेती की जाती है। विगत 2-3 वर्षों से जिले में मूँगफली का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और तिल, सोयाबीन एवं उड़द का क्षेत्रफल एवं उत्पादन जलवायु परिवर्तन के कारण घट रहा है। फसलों का चयन समय के अनुरूप माँग एवं जलवायु सहनशीलता कृषि पद्धति को अपनाकर फसलों के गिरते क्षेत्रफल एवं उत्पादकता को कम कर सकते हैं। उड़द की उन्नत



किसमें प्रजाप उड़द-1, आई.पी.यू. 94-1, मुकुन्दग, शेखर-2, शेखर-3, पी.यू.-30 आदि पीला मौजेक रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। मूँगफली की उन्नत किस्में टी.जी.-37ए, जे.जी.एन-23, आर.जी.-578, गिरनार-2, टी.जी.-39, जी.जी.-20 आदि। टी.जी.-37ए, टी.जी.-39, गिरनार-2, एच.एन.जी.-123, आर.जी.-578 आदि मुच्छेदार, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इन सभी में तेल की मात्रा 48 से 51 प्रतिशत तक है। तिल की अधिक उत्पादन वाली नई

किसमें टी.के.जी.-306 (दाना सफेद), टी.के.जी.-308 (दाना सफेद), जवाहर तिल-14 (काला बीज), जवाहर तिल-12 (दाना सफेद) आदि का चयन कर बीज की 1.5 से 2 कि.ग्रा. प्रति एकड़ व्यवस्था करें। सोयाबीन की नई किस्में के अंतर्गत जे.एस. 20-34, जे.एस. 20-29, आर.बी.एस. 2001-04, जे.एस. 20-69 एवं जे.एस. 20-98 आदि किस्में बहुरोग रोधी हैं। जे.एस. 20-69 एवं जे.एस. 20-34 कम पानी एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त हैं। मूँग की उन्नत किस्में सिखा, विराट, आई.पी.एम. 2-3, एम.एच.-421 आदि पीला मौजेक प्रतिरोधी एवं अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। सभी फसलों के बीजों को बुवाई से पूर्व बीजोपचार कार्बोक्सीन + थायरम दवा 2 ग्रा./कि.ग्रा. बीज की दर से उपचार कर बुवाई करें, जिससे बीज जनित फफूँदनाशक बीमारियों से फसल को बचाया जा सके। दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुवाई रिज्ड एवं फरी पद्धति या बी.बी.एफ. (चौड़ी क्यारी नाली) विधि से कतारों में बुवाई करने से कम पानी एवं अधिक पानी दोनों ही स्थिति में फसल सुरक्षित रहती है। जिले में अधिकारित: किसान छिडकवा विधि से बोते हैं इसलिए दलहन एवं तिलहन फसल में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दुधारू पशु का बीमा कराना फायदेमंद, तीन साल की पालिसी लेने पर मिलती है छूट

भोपाल।

पालतू जानवरों का बीमा कराने के प्रति पशुपालकों का रुझान उठाना नहीं है जितना होना चाहिए। जबकि पशुओं का बीमा पालकों के लिए लाभदायक और किफायती भी है। बीमा कंपनियों के आँकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 19-2020 के मुकाबले प्रीमियम की रकम में 65 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। सरकारी सामान्य बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2019-20 में मवेशी बीमा के माध्यम से 4.37 करोड़ रुपये की प्रीमियम आय हुई थी। 2021-22 में यह रेवेन्यू घटक 1.53 करोड़ रुपये रह गया है। इसी अवधि में ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्रीमियम आय 1.32 करोड़ रुपये से घटकर 40.02 लाख रुपये हो गई है।



जानिए क्यों घट रही दिलचस्पी- डेयरी उद्योग से जुड़े लोग तो पशुओं का बीमा कर रहे हैं।

दरअसल, डेयरी संचालक बैंकों से फंड लेकर जानवरों की खरीद करते हैं। इस स्थिति में बीमा अनिवार्य है। साधारण किसान बीमा में रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर, बीमा कंपनियाँ बिना भैसे के जानवरों का बीमा कराने में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। क्योंकि दावा करीब 400 फीसदी नुकसान का है। 50 हजार गायों का सालाना प्रीमियम करीब 200 हजार रुपए है। गाय का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में कंपनी दावे का भुगतान करने से इंकार नहीं कर सकती है।

टगी की भी संभावना है। तो एक गाय या भैंस बीमा कंपनी पर भारी पड़ती है।

प्रीमियम पर 25 से 40 प्रतिशत तक छूट- पशुओं का बीमा 4 प्रतिशत की दर से किया जाता है। यह एक ही राशि है और एक वर्ष के लिए है। तीन साल के बीमा पर 25 प्रतिशत की छूट। पांच साल के लिए 40 फीसदी तक की छूट मिल रही है।

100 में 10 दुधारू पशुओं का ही बीमा

इंस्टैंट ज़ोन जनरल इश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि 100 डेयरी पशुओं में से केवल 10 प्रतिशत का ही बीमा किया गया था। कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, भालू, घोड़े, बकरी, सूअर जैसे जानवरों के मामले में यह संख्या और भी कम है। डींग कीपर शैलेश कुमार ने कहा, मैं अकेला बीमित हूँ। कंपनी से बीमा लेने के लिए क्लेम का भुगतान करने में काफी दिक्कत आती है।

प्रदेश में तुअर, उड़द और मूंग का क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी

सायाबीन बोंवनी का लक्ष्य 51 लाख 72 हजार हेक्टेयर 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोंवनी संभावित

प्रदेश में लगातार बढ़ रहा दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्र

भोपाल।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में विविधीकरण के साथ दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ रहा है। इस वर्ष तुअर (अरहर), उड़द, मूंग सहित अन्य फसलों का क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोंवनी संभावित है। बात दें कि पिछले चार साल में तुअर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वहीं, सोयाबीन का क्षेत्र घटा है। इसकी जगह अब किसान धान की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं। मूंगफली, अलसी और सरसों का क्षेत्र भी बढ़ा है।



-34.71 लाख हेक्टेयर में धान की बोंवनी का लक्ष्य

सरकार ने इस वर्ष धान की बोंवनी के लिए 34 लाख 71 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में धान का सामान्य क्षेत्र 27 लाख 11 हजार हेक्टेयर है। पिछले वर्षों में किसानों ने सोयाबीन की जगह धान को प्राथमिकता दी है। सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में बासमती धान की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि इस वर्ष भी धान की बोंवनी अधिक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की है कि किसान एक तरह की फसल लेने की जगह विकल्प के तौर पर दूसरी फसल लें। उन्होंने कहा कि किसान हित में कृषि संचालनालय में प्रकोष्ठ गठित कर दिया गया है।

तुअर का क्षेत्र चार लाख 43 हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने तय किया है कि दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस वर्ष तुअर का क्षेत्र चार लाख 43 हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल दो लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तुअर की बोंवनी हुई थी। इसी तरह उड़द 15 लाख 97 हजार और मूंग की बोंवनी का लक्ष्य एक लाख 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

15 लाख चार हजार हेक्टेयर में मक्का बोंवनी का लक्ष्य

मक्का का लक्ष्य 14.16 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 15 लाख चार हजार हेक्टेयर रखा गया है। मूंगफली के लिए चार लाख 58 हजार और तिल की बोंवनी के लिए छह लाख 73 हजार हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है। उअर, सोयाबीन की फसल में पिछले कुछ सालों से किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए का क्षेत्र घटने की संभावना है। इसे देखते बोंवनी का लक्ष्य भी 55 लाख 31 हजार की जगह 51 लाख 72 हजार हेक्टेयर रखा गया है।

अमरूद से मालामाल होंगे किसान, मनरेगा में नवाचार
तीन साल में 5400 किसानों को
आत्मनिर्भर बनाने की कवायद

पेड़ को बिना काटे ही पुनर्जीवित किया जा सकता है
इजरायली तकनीक से पुराने
पेड़ों को मिलेगा नया जीवन



श्यापुर।

ग्राम पंचायतों द्वारा मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने के उद्देश्य से विभिन्न निर्माण कार्य कराने वाली मनरेगा योजना का पैसा अब खेती-किसानों में भी उपयोग किया जा सकेगा। यह नवाचार श्यापुर जिले में भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष श्यापुर जिले में 1800 गरीब किसानों को अपने खेतों में अमरूद के बाग लगाने के लिए 13 लाख 50 हजार पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने तीन वर्षीय इस योजना में 5400 किसानों को लाभांशित किया जाना है।

केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय ने श्यापुर को अमरूद जिले के रूप में प्रसिद्ध करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें अमरूद की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत मनरेगा मद से प्रथम चरण में इस वर्ष 1800 किसानों के बीच 13.50 लाख अमरूद के पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा मद से 10 करोड़ रूपए स्वीकृत भी कर लिए गए हैं। जिन किसानों को पौधों का वितरण किया जाना है उसमें पौधे रोपण के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल और सिंचाई के लिए ड्रिप योजना भी सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इस किसानों को यह लाभ दिया जाना है उनकी सूची एनआरएलएम के माध्यम से तैयार कर ली गई है।

फल देने तक करेंगे मदद

जिन किसानों को अमरूद के पौधों का वितरण किया जाएगा, उन्हें पौधे रोपण के लिए गड्डे खुदाई और बाउंड्रीवॉल का पैसा भी दिया जाएगा। पौधों का वितरण छोटे किसानों को ही किया जाना है, इसके लिए एक से दो बीघा भूमि वाले किसानों का चयन किया गया है। पौधरोपण के बाद उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल भी मनरेगा मद से कराई जाएगी। पौधों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई उपलब्ध हो, इसके लिए उद्यानिकी विभाग 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ड्रिप सिंचाई योजना हर खेत में उपलब्ध कराएगी। एनआरएलएम संबंधित किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के बड़े फॉर्म हाउसों में भ्रमण भी कराएगा।

मनरेगा मद से इस वर्ष 1800 किसानों को 13.50 लाख अमरूद के पौधे उपलब्ध कराएंगे। किसानों को अमरूद का बाजार मिले इसके प्रयास भी एनआरएलएम के माध्यम से करेंगे। तीन साल के इस प्रोजेक्ट में 5400 किसानों को लाभांशित किया जाएगा। डॉ. एसके मुदगल, डीपीएम, एनआरएलएम

भोपाल।

बागवानी करना व फलों के पेड़ों को लगाना एक बहुत ही अच्छा पेशा है। इस पेशे में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें से एक है पेड़ों के पुराने होने पर फल न देना। इस समस्या पर गौर करें तो हमें देखने को मिलता है कि कोई भी किसान या आम इन्सान फलों का पेड़ लगाता है तो एक तय समय के बाद उनमें फल आना बंद हो जाते हैं और वो पेड़ सिर्फ एक साधारण से पेड़ बनकर रह जाते हैं। इसके बाद बागवानी करने वाला व्यक्ति उन पेड़ों को या तो काट देता है या निराश होकर बागवानी करना ही छोड़ देता है। लेकिन इजराइल ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक तकनीक का विकास किया है, जिसके द्वारा पेड़ को बिना काटे ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता और फलों का आनंद दुबारा से लिया जा सकता है।

बागवानी केंद्रों उपलब्ध तकनीक- किसी भी बागवानी केंद्र से आप इस तकनीक को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तकनीक के जरिये पेड़ों को ठीक करवा सकते हैं।



ड़े गुना ज्यादा होगा उत्पादन

इस तकनीक में पेड़ की कटिंग तेजधार ब्लेड से की जाती है। क्योंकि कुल्हाड़ी से काटने पर पेड़ में घाव बनने का खतरा रहता है। यह तकनीक आम, आड़ू, अमरूद और बेर जैसे मोटे तने वाले पेड़ों में ही प्रयोग की जा सकती है। इस प्रक्रिया के बाद एक वर्ष में पेड़ फल देने लगता है और उत्पादन डेढ़ गुना अधिक हो जाता है। किसान को नया बाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इजराइल में बेकार एवं पुराने पेड़ों के लिए इसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

एक पेड़ पर 800 रूपये का खर्चा

इस इजरायली तकनीक के जरिये पेड़ों को दुबारा फल देने योग्य बनाने में प्रति पेड़ पर 800 रूपये का खर्चा होता है। लेकिन बजाय इसके बाद आपके पेड़ के फल न देने की समस्या का निदान हो जयेगा।

आम के पेड़ों पर चल रहा है इसका प्रयोग

इंडो-इजराइल के सहयोग से स्थापित सब्जी उकृष्टता केंद्र में इस तकनीक की मदद से 30 से 40 वर्ष पुराने आम के पेड़ों को नया जीवन दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक से पुराने फलदार पेड़ को कुछ शाखाओं को 6 से 7 फुट की ऊंचाई पर काट दिया जाता है। पेड़ के कटे हिस्सों पर कोपर आक्सिलोराइड और चूने का लेप लगाया जाता है। और कुछ दिनों बाद कनोपी मैनेजमेंट के जरिये पेड़ से नई स्वस्थ शाखाएं निकल आती हैं। एक वर्ष बाद पुराना पेड़ नए पेड़ में बदल जाता है और फल देने लगता है।



संजय माकवे
वरिष्ठ पत्रकार

तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद गेहूँ का संकट बना हुआ है। खासकर खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली गेहूँ की खरीद का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। गेहूँ की सरकारी खरीद 19 जून 2022 तक केवल 187.83 लाख टन ही हो पाई है। पंजाब में सबसे अधिक 96.47 लाख टन ही खरीद हो पाई है, जबकि पिछले साल 132.22 लाख टन हुई थी। पिछले 10 साल में सबसे कम खरीद हुई है। हरियाणा में केवल 41.61 लाख टन ही गेहूँ खरीदा जा सका है, जबकि पिछले साल 84.93 लाख टन खरीद हुई थी।

सरकारी खरीद लक्ष्य से दूर, खाद्य सुरक्षा पर संकट बढ़ा

इस साल देश में सरकारी गेहूँ की खरीद लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया है। सबसे कम गेहूँ उम में खरीदा गया है। यहाँ पिछले साल 56.41 लाख टन गेहूँ खरीदा गया था, लेकिन इस बार 3.31 लाख टन ही गेहूँ खरीदा जा सका है। मध्य में भी काफी कम गेहूँ खरीदा गया है। पिछले साल यहाँ 128.16 लाख टन गेहूँ खरीदा गया था, लेकिन इस बार केवल 46.03 लाख टन गेहूँ ही खरीदा गया है। राजस्थान में पिछले साल 23.40 लाख टन गेहूँ खरीदा गया था, लेकिन इस बार 19 जून तक केवल 9 हजार टन गेहूँ खरीदा गया है। गेहूँ की सरकारी खरीद में कमी के तीन बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं। एक तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद गेहूँ की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के कारण व्यापारी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत पर गेहूँ खरीद रहे हैं। दूसरा, इस मार्च और अप्रैल में भारी गर्मी के कारण गेहूँ का उत्पादन प्रभावित हुआ है और तीसरा, पिछले साल सरसों की फसल की कीमत अच्छी मिलने के कारण किसानों ने गेहूँ की बजाय बड़ी तादात में सरसों की बुआई की। हालात यह बन गए कि उत्तर प्रदेश में जब सरकारी खरीद काफी कम हुई तो सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन वे कारगर सिद्ध नहीं हुए। कम खरीद होते देख राज्य सरकार ने मोबाइल खरीद की भी प्रक्रिया शुरू की, जिसमें किसानों से कहा गया कि वे यदि सरकार को गेहूँ बेचना चाहते हैं तो सरकार अपने उनके गांव में जाकर खरीदने को तैयार है। बावजूद इसके किसानों ने इच्छा जाहिर नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद कम खरीद होते देख एक बार फिर से समय सीमा बढ़ा दी है। अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक गेहूँ की

खरीद होगी। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ खरीद कौन रहा है, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि किसानों से स्थानीय आदती ही संकरी कर रहे हैं और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक रेट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही गेहूँ उठाया जाता है, उसके साथ ही भुगतान कर दिया जाता है,



जबकि सरकारी केंद्र पर गेहूँ बेचने से किसान को भुगतान पांच से दस दिन के भीतर किया जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बनी स्थिति को देखते हुए व्यापारियों ने किसानों से ज्यादा कीमत पर गेहूँ खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने नियात पर रोक लगा दी तो व्यापारियों ने खरीद बंद कर दी थी और कीमत एमएसपी से कम हो गई थी, तब किसानों ने गेहूँ को बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से व्यापारियों ने अधिक कीमत पर गेहूँ खरीदना शुरू कर दिया, जिसके चलते किसानों ने सरकारी कीमत पर गेहूँ खरीदना शुरू कर दिया है। यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर गेहूँ के उत्पादन में कितनी कमी

आने की संभावना है। सरकार ने फरवरी 2022 में दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया था, जिसमें देश में 1113 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन मई में जारी अग्रिम अनुमान में केवल 5.6 प्रतिशत उत्पादन कम रहने की आशंका जताई गई, जबकि जानकारी का मानना है कि उत्पादन में 15 से 20 फीसदी तक का नुकसान हो सकता है। मलिक भी कहते हैं कि उत्पादन के अनुमान को लेकर सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उधर, 10 जून 2022 को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से एक बयान आया, जिसमें माना गया है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी खरीद के लिए गेहूँ की आवक कम रही, लेकिन सरकार ने इसमें भी अपनी तारीफ़ ढूंढ ली और कहा, देश भर में गेहूँ किसानों की उच्च बाजार दरों से लाभ हुआ, क्योंकि ज्यादातर अधिकांश किसानों ने अपनी उपज को एमएसपी की तुलना में उच्च बाजार दर पर निजी व्यापारियों को बेचा। जो कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस बयान में मंत्रालय की ओर से कहा गया, यह पाया गया है कि इस मौसम में

किसानों ने अपनी उपज औसतन 2150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेची है और इस तरह एमएसपी की तुलना में खुले बाजार में अपनी उपज बेचने पर उन्हें अधिक कमाई हुई है। इसी तरह, 444 लाख एमटी की अनुमानित खरीद पर, किसानों ने 2150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से औसतन लगभग 95,460 करोड़ रुपये कमाया होगा जबकि एमएसपी पर 2015 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से कमाई 89,466 करोड़ रुपये ही हुई होती। इस प्रकार गेहूँ किसानों को एमएसपी की तुलना में कुल मिलाकर 5994 करोड़ रुपये अधिक कमाई हुई होगी। हालांकि सरकारी खरीद न होने के कारण खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ गई है। सरकार ने सबसे पहले इस रबी सीजन में 444 लाख टन गेहूँ खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब किसानों ने गेहूँ व्यापारियों को बेचना शुरू किया और साथ ही मार्च में हुई भारी गर्मी की वजह से गेहूँ के उत्पादन में गिरावट की बात सामने आई तो सरकार ने मई के पहले सप्ताह में गेहूँ खरीद के लक्ष्य में संशोधन करते हुए चालू मार्केटिंग सीजन में 195 लाख टन कर दिया। यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है और अभी लगभग 187.88 लाख टन ही गेहूँ खरीदा जा सका है। चार मई 2022 को जब सरकार ने गेहूँ खरीद का लक्ष्य 195 लाख टन तय किया था, उस समय दावा किया था कि 1 अप्रैल 2023 को सरकार के पास 80 लाख टन गेहूँ होगा, जबकि रिजर्व स्टॉक 75 लाख टन होना चाहिए। लेकिन जैसा कि अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि अगर सरकार आने वाले दिनों में 190 लाख टन तक नहीं खरीद पाई तो सरकार के समक्ष रणनीतिक संकट पैदा हो सकता है।

स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है रासायनिक खादों व कीटनाशकों का पूर्णतः बहिष्कार

पिछले कुछ वर्षों में कोरोना या अन्य बीमारियों के हमले को देखते हुए अब हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। विकास की होड़ में हमने अपनी सभी पुरानी परंपराएं और पुरानी कृषि व्यवस्था को भूल चुके हैं। खासकर यदि खेती में देखा जाए तो हम रासायनिक खाद और केमिकल के भरोसे चल गए हैं, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है।

हमारे शरीर की मजबूती और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे द्वारा लिए जाने वाले आहार का। अन्न को यही ब्रह्म नहीं कहा गया है। हमारे अस्तित्व के सात तलों में से जो पहला तल है, यानी कि हमारा भौतिक शरीर, उसे योग की भाषा में 'अन्नमय कोष' कहते हैं। जो अन्न, यानी कि आहार से बनता हो वह होता है 'अन्नमय कोष', यानी कि हमारा भौतिक शरीर। आशा है अब आप समझ गए होंगे कि शुद्ध और पौष्टिक आहार को अपने शरीर को स्वस्थ व ऊर्जावान बनाए रखने में क्या अहमियत है। सबसे पहले हमें विचार करना है शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक भोजन कैसे प्राप्त हो। अभी समय के अभाव और आधुनिकता के कारण हम 'फास्ट फूड' अधिक ले रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम जो फल, सब्जी और अनाज खा रहे हैं उनको उगाने और पकाने में इतना केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारा पूरा भोजन ही जहर हो चुका है, जिसके कारण बीमार होते जा रहे हैं और हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर हो चुकी है कि हमारा शरीर किसी भी रोग से दो दिन भी नहीं लड़ पाता है।



भुनेश्वर त्रिपाठी
पत्रकार

तो यहां पर फिर एक सवाल आता है कि हमारे इतने आधुनिक और अमीर होने का क्या फायदा जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है? आप इतना समझ लीं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। यदि आपने अपने भोजन और अपनी जीवनशैली में परिवर्तन नहीं किया तो आगे और भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। अब वक है संभल जाने का। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द आप खेती के अपने वर्तमान तरीके को बदल लें और वापस अपने पूर्वजों के तौर-तरीकों को अपना लें, यानी कि फिर से बिना खर्च की और बिना जहर वाले तरीके बहुरसली खेती अपना लें। इसी बहुरसली प्रणाली में आपको सभी समस्याओं का हल है। हमें एकल फसल प्रणाली और

रासायनिक खेती से छुटकारा पाना होगा, तभी आपकी समस्याओं का हल निकलेगा। पहले अपने घर की जरूरत की हर चीज को अपने खेत में लगाएं और फिर बचे हुए रकबे में सरकार और बाजार के लिए उगाएं। अधिक से अधिक फसलें अपने खेत में लगाएं और रासायनिक खादों व कीटनाशकों की जगह देशी खाद व प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करें। अभी रासायनिक खादों व कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आज गांव-गांव तक कैंसर जैसी बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की एक नई समस्या से भी हमें दो-दो हाथ करना पड़ रहा है। रासायनिक खेती के कारण हम सिर्फ उत्पादन के लालच में एक या दो फसलों तक ही सीमित हो गए हैं। और भारत में यह स्थिति है कि एकल फसल प्रणाली के कारण किसान अपने परिवार की जरूरत का अनाज भी अपनी जमीन से पैदा नहीं कर पा रहा है, उसे अपने परिवार की खाद्य सामग्री के लिए भी बाजार जाना पड़ रहा है। इसका हल यही है कि हमें बहुफसली प्रणाली या मिश्रित खेती को अपनाना होगा, साथ ही रासायनिक खादों व कीटनाशकों का पूर्णतः बहिष्कार करना होगा। यदि आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और अपने परिवार को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। हमें फिर से अपने खेत में ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, अलसी, चना, मसूर, धनिया, मूंगफली एवं हर उस फसल का उत्पादन करना होगा जो हमारा परिवार इस्तेमाल करता है। हमें मोटे अनाज को अपने भोजन में इस्तेमाल करना होगा। हम सब को प्रकृति का सहायक बनना है, उसका दुश्मन नहीं। एकल फसल प्रणाली से तोबा कर लें और प्रकृति की रक्षा करने वाली प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें और रासायनिक खादों व कीटनाशकों का पूर्णतः बहिष्कार का संकल्प लें।

बेरोजगारी दूर करने का माध्यम एक्वाकल्चर

एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि, संयुक्त राष्ट्र के कृषि विभाग के अनुसार जल में उपस्थित पौधों और पशुओं का उत्पादन ही मुख्य रूप से एक्वाकल्चर कहलाता है आमतौर पर इस व्यवस्था को ज्यादातर मछली उत्पादन से जोड़कर लिया जाता है, जलीय जीव व जंतु के पालन पोषण को एक्वाकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर अंतर्गत प्रमुख जलीय जीव जैसे मछली, मोलस्का, शंख, जलीय जीव, शैवाल इत्यादि आते हैं। इनके पालन पोषण की प्रमुख आवश्यकता में इनकी अधिक उत्पादकता बढ़ाना, इनका भोजन व सुरक्षा आदि सम्मिलित हैं। अगर बात कि जाए समुद्री वातावरण कि तो समुद्र में एक्वाकल्चर को मुख्यतः 'मेरीकल्चर' कहा जाता है, एक्वाकल्चर में मुख्य रूप से मत्स्य पालन, शैवाल पालन और सजावट हेतु उपयोगी और महत्वपूर्ण जलीय जीव जंतुओं एवं पदार्थों का पालन, उनका भोजन तथा उनका सुरक्षा का मुख्य कार्य किया जाता है। यह जलीय जीव हमारे भोजन में प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होते हैं। अगर हम एक्वाकल्चर कि बात करें तो इसके अन्य फायदे हैं। एक्वाकल्चर मुख्य रूप से, मछली की उत्पादन तथा आबादी को प्रजनन के लिए अनुमति प्रदाय करता है। एक्वाकल्चर का महत्व: अगर हम बढ़ती जनसंख्या, भुखमरी तथा शुद्ध पौष्टिक आहार की कमी के अभिप्राय में बात करें तो एक्वाकल्चर का महत्व तथा मांग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आज ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग बेरोजगारी दूर करने का माध्यम बना लिए है एक्वाकल्चर बहुत ही कम समय एवं कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाले एक मात्र सरल व्यवसाय के रूप में लिया जा रहा है। यह एक लाभप्रद और मुनाफा देने वाली खेती है जिसे किसानों को उभर आती बहुत ही आसानी व सरलता से कर सकता है न्यूक्ति न तो इसमें अधिक मजदूरी लगती है और न ही जल्दी बीमारी से बचना होता है इसमें हमें सीस की भी इंजात नहीं करना होता है और न ही इसमें ओला और पला का डर होता है, अगर इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते तो हमें हमारे उत्पादन के अनुसार मूल्य मिल जाता है और इसमें आकार मापक के अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाता है। एक्वाकल्चर को मुख्यतः तीन प्रकार में बाटा जा सकता है। मीठे पानी, समुद्री और खारे। अगर बात करें मीठे पानी का तो इसको मुख्यतः नदियों, झीलों और तालाबों में करते हैं। समुद्री जलीय कृषि यह मुख्यतः खुले महासागर, इंटरकोस्टल क्षेत्रों और समुद्री तैंगन में मुख्य रूप से किया जाता है। ब्रिटीश एक्वाकल्चर मुख्यतः जलीय वातावरण किया जाता है जोकि आमतौर पर पानी ताजा और खारे पानी का मिश्रण होता है। एक्वाकल्चर महत्वपूर्ण वयों है: अगर बात कि जाए एक्वाकल्चर कि तो ये उच्च गुणवत्ता वाले, स्वस्थ पशु प्रोटीन का एक अच्छा और मुख्य स्रोत प्रदान कर सकते हैं और जैसे कि हम जानते है कि आमतौर पर स्थलीय पशु कृषि की तुलना में एक छोटी भूमि, कार्बन और पानी के उपयोग के पदविह होते एक्वाकल्चर एक बढ़ती हुई आबादी के लिए सीफूड की प्रमुख आपूर्ति बन जाएगा। एक्वाकल्चर एक वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है जो उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रोटीन का उत्पादन कर सकता है, जब सही तरीके से किया जाता है, तो एक स्थायी पदविह हो सकता है। एक्वाकल्चर के उपयोग: संसार के मुख्यतः लोग मछली को भोज्य पदार्थों में प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत मानते है और इसपर निर्भर भी रहते है। एक्वाकल्चर का मुख्यतः एक अच्छा महत्व व्यवसायिक स्तर पर भी है। संसार के अधिकांश लोग प्रोटीन के अच्छे स्रोत के लिए मछली एवं समुद्री जीवों का क्रय मुख्यतः भोजन हेतु करते हैं। मुख्यतः एक्वाकल्चर का उपयोग कृषि अनुपयोगी भूमि का सदुपयोग करने के लिए भी किया जाता है। मछली का तेल जो इस प्रकार है इसको सोपेनॉइड अम्ल, ओमेगा-3 फैटी अम्ल और डीएनए का प्रमुख स्रोत है। मछली के तेल और मांस का प्रयोग मुख्यतः उर्वरक व रूफ में भी किया जाता है। कुछ मछली जैसे सितारा मछली, समुद्री अर्चिन, दरियाई घोड़ा, और समुद्री खीरे पारंपरिक चीनी दावा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। केल्य मछली का मुख्यतः उपयोग खाद्य और कौन बनाने में उर्वरक के रूप में किया जाता है तथा इसके अलावा यह आयोडीन का भी अच्छा स्रोत है।

दक्षिणी भारत में पूरे सालभर की जाती है इसकी खेती

फ्रेंच बीन की खेती: लोकप्रिय किस्में, जो कम समय में देंगी ज्यादा उत्पादन

भोपाल।

दलहनी कुल की सब्जियों में फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती हमारे देश के सम्पूर्ण मैदानी क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में व पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में की जाती है। दक्षिणी भारत में इसकी खेती पूरे वर्ष की जाती है। फ्रेंचबीन की हरी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में तथा सूखे दानों का उपयोग दालों के रूप में किया जाता है। इसकी हरी फलियों व सूखे दानों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कैरोटीन, विटामिन्स व फोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाते हैं। भारत में इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और पर्वोत्तर राज्यों में सफलतापूर्वक की जाती है। फ्रेंच बीन की कुछ किस्में, जो 70 से 100 दिनों में 20 से 24 टन/हेक्टेयर तक उपज दे सकती हैं।

उपयुक्त जलवायु

फ्रेंचबीन मूलतः सम जलवायु की फसल है। अच्छी बहवार व उपज के लिए 18 से 20 डिग्री सेन्टीग्रेट तापमान उपयुक्त होता है। 16 डिग्री सेन्टीग्रेट से कम व 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम का फसल की वृद्धि व उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की फसल पाला व अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है।

भूमि का चयन

फ्रेंचबीन की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई-दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसका पी एच मान 6 से 7 के मध्य हो फ्रेंचबीन की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल ठहराव की अवस्था इस फसल के लिए अति हानिकारक होती है।



खेत की तैयारी

यदि खेत में नमी की कमी हो तो बुवाई से पूर्व खेत का पलेंवा कर लेना चाहिए। बुवाई के पूर्व खेत की अच्छी तरह जुताई व पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। बुवाई के समय बीज अंकुश के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है।

उत्तम किस्में

फ्रेंचबीन की खेती के लिए किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उपज वाली किस्म चयन के साथ-साथ विकार रोधी का उपयोग करना चाहिए। कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार हैं, जैसे-

बौनी किस्में- कटेन्डर, पूसा पार्वती, वी एल बोनी-1, काशी परम, काशी समग्र, काशी राजहंस, अर्को सुविधा, पन्त अनुष्मा, प्रीमियर और अर्को कोमल आदि प्रमुख हैं।

बेलनुमा किस्म- पूसा हेमलता, स्वर्ण लता, एस वी एम-1, लक्ष्मी (पी-37) और केन्दुकी वन्दर आदि प्रमुख हैं।

अकरा अर्जुन/अकरा अर्जुन एक

झाड़ीदार, मजबूत और असंवेदनशील किस्म है। यह रबी और गर्मी दोनों के लिए उपयुक्त है। यह मृग येले मोजेक वायरस रोग के लिए प्रतिरोधी है। यह किस्म 70 दिनों में 17 टन प्रति हेक्टेयर उपज देती है।

अकरा अनूप/अकरा अनूप एक झाड़ीदार और असंवेदनशील किस्म है। इसकी फली लंबी, सपाट और सीधी होती है। यह जंग और बैक्टीरियल ब्लाइट रोग दोनों की प्रतिरोधी किस्म है। इस किस्म की उपज 70-75 दिनों में 20 टन/हेक्टेयर होती है।

अकरा बोल्ड/अकरा बोल्ड असंवेदनशील और झाड़ीदार किस्म है। इस किस्म की फली चपटी, मांसल, कुरकुरी, अतिरिक्त बड़ी (16 सेमी) और लंबाई में मध्यम होती है। यह जंग रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है। इस किस्म की उपज 70 दिनों में 15 टन प्रति हेक्टेयर है।

अकरा कोमल/अकरा कोमल झाड़ीदार, प्रकाश-असंवेदनशील किस्म है। यह किस्म की फली सीधी, लंबी और सपाट होती है। यह जंग और बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोध दोनों है। इस किस्म की उपज 70-75 दिनों में 20 टन/हेक्टेयर होती है।

यह किस्म की फली सीधी, लंबी और सपाट होती है। यह जंग और बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोध दोनों है। इस किस्म की उपज 70-75 दिनों में 20 टन/हेक्टेयर होती है।

अकरा सुकोमल/अकरा सुकोमल उच्च उपज देने वाली जंग प्रतिरोधी पोल बीन किस्म है। इस किस्म के पौधे अनिश्चित होते हैं और 2.0 मीटर से अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। पहली फसल के लिए किस्म को 60 दिन लगते हैं। इस किस्म की फली कड़े, अंडाकार, हरी और लंबी (23 सेमी) होती है। यह किस्म खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस किस्म की उपज 100 दिनों में 24 टन/हेक्टेयर होती है।

बीज की मात्रा/फ्रेंचबीन की बौनी (झाड़ीनुमा) किस्मों के लिए 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और लता वाली किस्मों के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है।

बीजोपचार

फ्रेंचबीन के बीज को बुवाई से पहले फफूंदनाशी रसायन कार्बेन्डाजिम की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी चाहिए। इससे फसल की प्रारम्भिक अवस्था में मिट्टी जनित बीमारियों से सुरक्षा हो जाती है।

बुवाई का समय

उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फ्रेंचबीन (फ्रांसबीन) की बुवाई का सबसे उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 07 नवम्बर तथा तराई क्षेत्रों में फरवरी से मार्च है। पहाड़ी क्षेत्रों में फ्रेंचबीन की खेती ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में की जाती है। इसके लिए कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में फरवरी से मार्च व अमरत का महीना, मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में मार्च से जुलाई और अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अप्रैल से जून का समय सर्वोत्तम होता है।

बुवाई की विधि

बीज की बुवाई उठी हुई मेड़ों या क्यारियों में बुवाई करना पौधों की अच्छी वृद्धि व अधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है। झाड़ीनुमा (बौनी) किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा कतार में पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। लता वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 75 से 100 सेंटीमीटर तथा कतार में पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं।

खाद और उर्वरक

अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले या बुवाई के समय आधारीय खुराक के रूप में देते हैं। नाइट्रोजन की शेष मात्रा दो बार भागों में बँटकर बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन व 35 से 45 दिन बाद टाप ड्रैसिंग के रूप में देना चाहिए।

पैदावार

फ्रेंचबीन की फसल से पैदावार किस्म चयन, खाद और उर्वरक की मात्रा, फसल देखभाल और अन्य कृषि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन सामान्यतः उपरोक्त वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर फ्रेंचबीन की झाड़ीनुमा (बौनी) किस्मों से हरी फलियों की उपज 80 से 230 कुन्तल व लता वाली (बेल) किस्मों की 80 से 250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है। सूखे दानों की औसत उपज 10 से 21 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है।

वैज्ञानिकों ने खेत पर भ्रमण कर प्राकृतिक खेती की दी सलाह कार्यक्रम में बताया योग का महत्व



टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस. किरार साथ ही केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. यू.एस. धाकड़ एवं डॉ. सुनील कुमार जाटव द्वारा विकासखंड जतारा के ग्राम लिथोरा ताल में कृषक बालचंद्र अहिरवार के खेत में भ्रमण किया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने उन्नत खेती और उसके रखरखाव की जानकारी भी दी। जिसमें अनार की पौधों की देख रेख एवं पक्षियों से बचाने के लिए फलों पर कवर लगा कर उन को खाने से बचाया जा सके। अनार के खेत में पौधों

से पौधों की दूरी का सदुपयोग कैसे करें। खरीफ मौसम में अनार के पौधों के बीच अंतरवर्ती मृगफली, अरहर, उर्द एवं तिल की फसल को उगाया जा सकता है। इन फसलों के अलावा कंद वाली फसलें जैसे अदरक, हल्दी और अन्य फसलों को उगाया जा सकता है, जिससे किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सके जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। साथ ही किसान को प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हुये उन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

रीवा। कृषि महाविद्यालय रीवा में दिनांक 21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं एन.सी.सी. इकाई के समन्वय से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. एस.के. पयासी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा रहे एवं विषय अतिथि के रूप में डॉ. सरोज सोनी आरोग्य भारती के सदस्य उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सरस्वती जी की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, इसके पश्चात डॉ. ए.एस. चौहान एन.एस.एस.प्रभारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। डॉ. रघुराज तिवारी एन.सी.सी. प्रभारी द्वारा सरोज सोनी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया।

डॉ. चौहान ने कार्यक्रम का महत्व बताते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर योग विशेषज्ञ डॉ. एस.एम. कुर्मवंशी प्रमुख वैज्ञानिक ने योग एवं प्राणायाम की विधियों की समझाएश दी एवं इसके करने से होने वाले लाभों को भी बताया। डॉ. एस.के. पयासी मुख्य अतिथि



ने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ रहना है तो योग एवं प्राणायाम से नियमित रूप से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र, छात्राएं, प्रोफेसर वैज्ञानिक, कर्मचारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. अजय पाण्डेय सहित सभी वैज्ञानिक ने भाग लेकर योग एवं प्राणायाम किया। डॉ. एस.एम. कुर्मवंशी ने प्राणायाम के सभी क्रियाओं को करके दिखाया एवं सभी सहभागियों ने उसे किया। इस कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय के डॉ. ए.के. जैन, डॉ. आर.पी. जोशी, डॉ. टी.के.

सिंह, डॉ. ए.के. गिरी, सुधीर सिंह एवं हरीश द्विवेदी की उपस्थिति सराहनीय रही। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र रीवा से वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. रिमता वैज्ञानिक, कर्मचारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र ने उपस्थिति देकर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में नाबाई से सुनील डीगले ने भी भाग लिया। अन्त में डॉ. रघुराज किशोर तिवारी प्राध्यापक एवं एन.सी.सी. प्रभारी ने मुख्य अतिथि विषय अतिथि वैज्ञानिकों एवं सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया।

प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसल के नुकसान में लें पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसल के नुकसान में लें पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

नई दिल्ली,

खेती-किसानी के दौरान किसान की फसल कभी-कभार बारिश-ओले या आंधी तूफान की वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में कई किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ जाता है। किसानों का बीमा नहीं होने की वजह से वे बर्बाद फसल पर मुआवजा भी नहीं ले पाते हैं। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसान को यदि व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ मिलता था। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भरपाई बीमा कम्पनी के तहत मिल जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वे किसान भी होंगे, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ या बनवाया गया है या सहकारी बैंक का कर्जा नहीं है। वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ई मित्र या क्रियोस्क या अन्य किसी माध्यम से फसल बीमा करवाया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, बंटईदार किसानों को शामिल किया जाएगा। बंटईदार किसानों को संबन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि कृषक जिस जिले का निवासी है उस परिधि क्षेत्र में बंटई की भूमि ही मान्य होगी।



ऋणी किसान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि द्वारा अधिसूचित इकाई क्षेत्र एवं उस क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल के लिए तय समय सीमा के अधीन बीमा करवाना अनिवार्य है। किसानों द्वारा फसल बीमा करवाना पूर्णतः स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी किसानों को योजना से अलग रहने के लिए अंतिम तारीख से 7 दिवस पहले तक संबंधित बैंक में जाकर इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस योजना के तहत किसान के खाते से प्रीमियम काटा जाएगा।

गैर ऋणी कृषक

गैर ऋणी किसान किसी भी नजदीकी बैंक से बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेंट और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत फसल बीमा करवा सकते हैं।

कितना देना होगा प्रीमियम

खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक/ बागवानी फसलों के किये प्रीमियम क्रमशः 2, 1.5 एवं 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

गैर ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज

- बीमा हेतु प्रस्तुत क्षेत्रफल में बोई गई/बोई जाने वाली फसल की स्वयं प्रमाणित नवीनतम जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत करनी होगी।
- स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसमें प्रत्येक खसरे का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित खसरे का क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा का प्रकार (स्वयं, परिवार अथवा बंटई) अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक पासबुक की प्रतिलिपि उपलब्ध करवानी होगी।
- बंटईदार किसानों को खेत के मालिक से एक प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा एवं कृषक को अपना मूलनिवास प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- बंटईदार किसान एवं खेत के मालिक को अपनी आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करवानी होगी।
- बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट/प्रतिनिधि गैर ऋणी एवं बंटईदार कृषक से प्रीमियम नकद में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान नेफ्ट/आरटीजीएस के

माध्यम से ही करना होगा।
 गैर ऋणी किसान को देय बीमा क्लेम का भुगतान बैंक के माध्यम से संबंधित कृषक के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरित किया जायेगा।

कब मिलेगा बीमा का लाभ

- कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से बुवाई नहीं होने की स्थिति में (निष्फल बाधित बुवाई) खरीफ फसलों में लिए।
- खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) में बाढ़, लंबी अवधि तक सूखा, जलप्लावन, कीट, व्याधि, जलप्लावन, आकाशीय बिजली से आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण उपज में हुए नुकसान को इसमें कवर किया जायेगा।
- फसल कटाई उपरान्त सूखने के लिए खेत या खलिहान में रखी फसल को चक्रवात, चक्रवर्ती बरसात, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई उपरान्त अधिकतम 14 दिवस की अवधि तक बीमा मान्य है।

जन समर्थ पोर्टल से उठाएं कई सरकारी योजनाओं का लाभ

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए करें आवेदन, 4 जुलाई अंतिम तारीख

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जून को जन समर्थ नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। जन समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जो तेरह क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता

है। वर्तमान में चार ऋण की श्रेणियां हैं इनमें शिक्षा, कृषि, व्यवसाय और दीनदयाल योजना शामिल है। और हर श्रेणी में विभिन्न योजनाएं हैं। पोर्टल पर अपनी पात्रता की जांच करें और आवेदन करें।

नई दिल्ली।

देश के किसानों की आय दोगुनी करने और उनके हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही इन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक ऐसी योजना है जो खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान देगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य एक व्यापक पैकेज की पेशकश करना है।

ये योजना भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। इससे ये भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करेगी, जिससे रोजगार भी पैदा होगा। एकीकृत कोल्ड चेन यानी फसल फार्म गेट से डायरेक्ट रिटेल आउटलेट तक कुशल सप्लाई होगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण या विस्तार होगा। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचा देना इस योजना की प्रमुख खासियत है। भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की इन उप-योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किया है।



- कृषि प्रसंस्करण समूहों (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना।
- खाद्य प्रसंस्करण और बचाव संबंधी क्षमताओं के निर्माण/विस्तार के लिए योजना (यूनिट स्कीम) (सीईएफपीपीसी)।
- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन) के लिए योजना।
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल)।
- ऑपरेशन

- ग्रीन्स (ओजी)
- भावी प्रमोट/निवेशक/उद्यमी जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सुविधाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए पात्र और इच्छुक हैं 27 जून 2022 को सुबह 10 बजे से <https://sampa-da-mofpi.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल)।
- ऑपरेशन

- दिशानिर्देशों के अनुसार जमा करना होगा।
- प्री-विड बैकट 4 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे कमरा नंबर 120, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
- मूल डिमांड ड्राफ्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर मंत्रालय पहुंच जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022, शाम 17.00 बजे तक है।

सरकारी योजनाएं

- केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना
- पट्टे परदेश-विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना
- डॉ. अम्बेडकर केन्द्रीय क्षेत्र योजना

कृषि आधारित संरचना ऋण

- कृषि वृत्तीय और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना
- कृषि विपणन अवसंरचना
- कृषि अवसंरचना कोष

व्यवसायिक गतिविधि ऋण

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन
- बुनकर मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना
- सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना
- स्टैंड अप इंडिया योजना

अपने आवेदन की ट्रैकिंग करें

- आवेदक वेब पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
- जन समर्थ पोर्टल का लाभ
- लोन के लिए आवेदक को बैंकों के चक्र नहीं लगाने होंगे। पात्र होने पर ऑनलाइन मंजूरी दी जाएगी।
- ऑनलाइन ही अपने आवेदन पर होने वाली कार्रवाहों को देख सकेंगे।
- सभी सरकारी बैंक के साथ 125 विभिन्न वित्तीय संस्थान इस पोर्टल से जुड़े हैं।
- लोन लेने के इच्छुक आवेदक के आवेदन को इन सभी वित्तीय संस्थानों के पास ऑनलाइन भेज दिया जाएगा।
- फिलहाल चार श्रेणी के लोन के लिए आवेदन की सुविधा होगी। इसमें शिक्षा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारोबार, शुरुआत एवं जीवनयापन लोन शामिल है।
- आवेदक लोन नहीं मिलने पर या आनाकानी करने पर उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकेंगे।
- 3 दिनों में शिकायत का निपटारा करना होगा।
- भविष्य में इस पोर्टल का और विस्तार किया जाएगा।

किसान अधिक पैदावार के लिए लगाए बासमती धान की यह उन्नत किस्में

बासमती
धान की
उन्नत किस्में

किसान अधिक पैदावार के लिए लगाए बासमती धान की यह उन्नत किस्में



भारत में खरीफ मौसम में धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है, अधिकांश किसानों के लिए धान उत्पादन ही मुख्य रूप से उनकी आजीविका का साधन है। देश में धान का उत्पादन लगभग 128 मिलियन टन तक होता है। वहीं देश में धान की 1000 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं जिनकी खेती की जाती है, परंतु वैज्ञानिक लगातार किसानों के लिए नई उन्नत किस्में विकसित कर रहे हैं। किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित की गई बासमती धान की किस्मों के विषय में जानकारी लेकर आया है। किसान अपने क्षेत्र एवं जलवायु के अनुसार उपयुक्त प्रजाति का चयन कर धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं।

पूसा 1592 पूसा 1592 धान की उन्नत किस्म को सिंचित क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है। यह मध्यम देरी 120 दिन में पकने वाली फसल की किस्म है, इसका दाना पतला तथा लम्बा होता है। यह किस्म झुलसा रोग के प्रति सहनशील है। इस किस्म का औसत उत्पादन 47.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अधिकतम उत्पादन 67.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर राज्यों के लिए है।

पूसा बासमती 1609 पूसा बासमती 1609 किस्म को सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, इसके दाने लंबे, पतले तथा अधिक सुगंधित होते हैं। यह किस्म मध्यम देरी (120 दिन) में तैयार होने वाली प्रजाति में जानी जाती है। इस किस्म का औसत उत्पादन 46.0 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा अधिकतम उत्पादन 67.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा बासमती 1609 धान की प्रजाति को बासमती खेती वाले क्षेत्र (उत्तराखंड, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के लिए अनुमोदित किया गया है।

पूसा बासमती 1637 यह प्रजाति को सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। यह माध्यम देरी (130 दिन) से पकने वाली प्रजाति के रूप में जानी जाती है 7 यह प्रजाति झोंका रोग के लिए प्रतिरोधक है 7 इसके दाने सुगंधित और लंबे तथा पतले होते हैं 7 इस प्रजाति के धान का औसत उत्पादन 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अधिकतम 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है 7 पूसा बासमती 1637 धान की प्रजाति को बासमती की खेती वाले क्षेत्र (पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के लिए अनुमोदित किया गया है 7

पूसा बासमती 1728 पूसा 1728 किस्म को सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, यह किस्म देर से (140 दिन) पकने वाली प्रजाति में जानी जाती है 7 यह किस्म झुलसा रोग के प्रति सहनशील है 7 इस किस्म का औसत उत्पादन 41.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जबकि अधिकतम उत्पादन 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा

बासमती 1728 किस्म की खेती बासमती क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। इस किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर राज्यों में की जा सकती है।

पूसा बासमती 1718 पूसा बासमती 1718 किस्म को सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, यह अधिक समय (135 दिन) में पक कर तैयार होने वाली प्रजाति है। यह किस्म झुलसा रोग के लिए प्रतिरोधक है। इसके दाने अधिक सुगंधित के साथ-साथ लंबे होते हैं। इसका औसत उत्पादन 46.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अधिकतम उत्पादन 60.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान की इस किस्म की खेती बासमती की खेती वाले क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए अनुमोदित किया गया है।

पूसा बासमती 1692 पूसा बासमती 1692 धान को सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, यह कम समय 115 दिन में तैयार होने वाली प्रजाति है। इसके पौधे मध्यम आकार के होने के साथ ही साथ धान के दाने लंबे तथा पारभासी होते हैं। इसके दाने खुशबूदार होता है। पूसा बासमती 1692 प्रजाति के धान का औसत उपज 52.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अधिकतम 73.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा बासमती 1692 धान की खेती दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा सकती है।

पूसा सांबा 1850 पूसा सांबा 1850 प्रजाति को सिंचित क्षेत्र के लिए ज्यादा उतम माना गया है। धान की यह किस्म झोंका रोग के प्रति सहनशील है। इसके दाने मध्यम पतले 5.6 मिमी. के होते हैं। इस प्रजाति की उपज अधिक समय (140 दिन) में पकने वाली है। इस प्रजाति के धान का उत्पादन औसत 47.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा अधिकतम उत्पादन 69.0 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा सांबा 1850 प्रजाति का अनुमोदन ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुमोदित किया गया है।

पूसा बासमती-1121 पूसा बासमती की 1121 किस्म को

2005 में रिलीज किया गया था। इस चावल की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा होना है। जानकारी के मुताबिक 1121 चावल का साइज 12 एमएम से भी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक चावल एक्सपोर्ट में 1121 चावल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 1121 धान की औसत पैदावार 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अधिकतम पैदावार हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 1121 धान में सुधार करके नई किस्म पूसा बासमती 1718 आई है। नई किस्म में बीएलबी (बैक्टिरियल लीफ ब्लाइट) नामक बीमारी नहीं लगती है। हालांकि बाकी सभी खासियत एक जैसी ही है।

पूसा बासमती 1509 पूसा बासमती 1509 किस्म सात से आठ साल पुरानी है। 1509 धान को बहुत कम समय में पैदा किया जा सकता है। इसके पैदावार में बुआई से लेकर कटाई तक 110-115 दिन का समय लगता है। 1509 का औसत उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हालांकि अधिकतम 65 क्विंटल तक उत्पादन किया जा सकता है। कम अवधि में पैदा होने की वजह से यह धान किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में बुआई के लिए 1509 एक अच्छी किस्म मानी जाती है।

पूसा बासमती-1637 पूसा बासमती-1637 करीब 2 साल पुरानी किस्म है। इस किस्म को यूरोप और अमेरिका में काफी पसंद किया जाता है। दरअसल, इस किस्म में कम बीमारी लगती है इसलिए कीटनाशक का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। पूसा बासमती-1637 की बुआई से लेकर कटाई तक 140 दिन का समय लगता है। इस धान की औसत पैदावार 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा पूसा बासमती 6 (पूसा 1401), पूसा 1460, सुगंधा बासमती और पूसा बासमती 1 बासमती की बेहतरीन किस्में हैं। इन किस्मों की फसल लगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

अन्य किस्मों की तुलना में काले चावल में रोग एवं कीटों का प्रकोप कम, विशेष गुणों के चलते विदेशों में काफी मांग

औषधीय गुणों वाले काले धान की खेती कर देगी मालामाल

भोपाल। इन दिनों किसान परंपरागत खेती छोड़कर अधिक आय देने वाली पवडसलों की खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस समय काले चावल की खेती की खूब चर्चा है। काले चावल को मांग विदेशों तक है। इस चावल में के टेरों औषधीय गुण होते हैं। अन्य किस्मों की तुलना में काले चावल में रोग एवं कीटों का प्रकोप कम होता है। इसकी खेती में लागत भी अन्य की कम आती है। अधिक मूल्य पर बिक्री होने के कारण अधिक मुनाफा होता है। केवल जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद का प्रयोग कर के भी हम बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं। पौधों में दानों से भरी हुई लम्बी बालियां आती हैं। कई पोषक तत्वों से भरपूर होने

के कारण इसकी कीमत अधिक होती है। इसलिए काले चावल की खेती करने वाले किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

कुछ वर्षों पहले तक काले चावल की खेती केवल मणिपुर और असम में की जाती थी। लेकिन अब इसकी खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आदि कई राज्यों में सफलतापूर्वक की जा रही है। काले चावल में चाय एवं कॉफी से अधिक मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके साथ ही काले चावल में सफेद चावल और ब्राउन राइस से अधिक मात्रा में विटामिन बी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नेशियम, जिंक, आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं।



वैज्ञानिक विधि से करें काले चावल की खेती

-कब करें रोपाईं जून-जुलाई के महीने में इसक रोपाईं की जाती है। अन्य किस्मों की तुलना में काले चावल की फसल को तैयार होने में अधिक समय लगता है। इसे पककर तैयार होने में लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं।

-कम पानी में की जा सकती है खेती इसके पौधे मजबूत होते हैं, जिससे पौधों के टूटने की समस्या नहीं होती है। पौधों की लम्बाई करीब 6 फीट तक होती है। इसकी खेती कम पानी में संभव है।

-काले चावल के औषधीय गुण

काले चावल का सेवन हृदय रोग एवं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में सहायक है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। 10 ग्राम काले चावल में करीब 9 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसमें फाइबर और आयरन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह मधुमेह (डायबिटीज) के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है।

काला चावल की खेती में लागत और कमाई

काले चावल की खेती में लागत सामान्य धान की तुलना में कम ही लगता है क्योंकि यह काला धान की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। सफेद और ब्राउन राइस की तुलना में इसकी कीमत भी बाजार में अधिक मिलता है। काला चावल सामान्य तौर पर 400 से 500 रूपए प्रति किलो बिक जाता है। जबकि सामान्य चावल का दाम 25 से 80 रूपए प्रति किलो से अधिक नहीं मिलता है।

